RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 31 जनवरी, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 9, अंक : 8

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

हमें आशा है कि पूरी शक्ति के साथ आप वर्ष 2013 के भण्डारण के लिए तैयार हो चुके होंगे। आपने अपने यहाँ की मशीनरी, बिल्डिंग आदि की मरम्मत सही प्रकार से करवा ली होगी। सारे वाल्व की चेकिंग, ट्रांसफार्मर, ऑयल की चेकिंग, पानी के टैंक की सफाई, इन्सूलेशन की मरम्मत आदि मुख्य बातें हैं जो जरूर देख ली होगी। इसके साथ ही आग बुझाने के संयंत्र व आपातकालीन अमोनिया लीक पर नियंत्रण आदि की परीक्षा भी कर ली गई होगी। यदि कोई भी चीज छूट गई है तो उसे अभी ठीक करा लें। अपने यहाँ के वजन करने वाले कांटे भी नाप तौल विभाग से जँचवा लें।

जहाँ तक विभिन्न जनपदों से वा अन्य प्रदेशों से आलू उत्पादन के बारे में जो समाचार मिल रहे हैं वा सरकार द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनसे यह अनुमान लग रहा है कि इस वर्ष आलू का उत्पादन गत वर्ष के अनुपात में कम से कम 20 प्रतिशत ज्यादा है। अतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी शीतगृह पूरी तरह भर जायेंगे। इसके साथ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिक आलू भण्डारित होने के कारण शीतगृहों को समय

रहते पूरी तरह खाली हो जाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। शीतगृहस्वामियों को यह सलाह दी जा रही है कि वह आलू पर लोन बहुत सोच समझ कर बाँटे।

29 जनवरी, 2013 को हुई मीटिंग के सम्बन्ध में :

होटल क्लार्क अवध, लखनऊ में 29 जनवरी, 2013 को कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा मीटिंग आयोजित की गई। यह मीटिंग मुख्यतः शीतगृह भण्डारण प्रभार वर्ष 2013 पर विचार–विमर्श व सलाहकारी रेट बताने के बारे में आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त विद्युत भार, Warehousing Development Regulation Act 2007 (WDRA Act 2007), फूड सेफ्टी

बायें से दायें : **श्री अनन्त राम अग्रवाल, श्री महेन्द्र स्वरूप, श्री मोहम्मद अकरम, श्री रमा शंकर अवस्थी**

मीटिंग में उपस्थित सदस्यगण

एक्ट के बारे में भी चर्चा की गई। यहाँ पर अच्छी संख्या में शीतगृहस्वामियों ने हिस्सा लिया। ठण्ड के हालात देखते हुए 150 के करीब लोगों की उपस्थिति सराहनीय थी। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस मीटिंग में युवा पीढ़ी ने बहुत उत्साह दिखाया और अपनी उपस्थिति दर्ज की।

श्री रमा शंकर अवस्थी, जो हमारे बिजली सलाहकार भी हैं, ने विद्युत सम्बन्धी विभिन्न विवादों पर प्रकाश डाला जो कि ट्रिब्यूनल या विद्युत नियामक आयोग में चल रहे है। श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि शीघ्र ही उपभोक्ताओं पर ईंधन अधिभार लगाया जाना प्रायः निश्चित हो चुका है। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों का विद्युत पर बोझ हर तीन माह बाद उपभोक्ताओं पर लगाया जाना प्रस्तावित है जो कि आगामी तीन माह में लग जाना संभावित है। इसके बाद श्री अवस्थी जी ने यह भी बताया कि 10 के.वी.ए. से ऊपर के किसी भी प्रकार के विद्युत कनेक्शन पर पावर फैक्टर पेनाल्टी लगाए जाने का भी प्राविधान है।

सरकार WDRA के अर्न्तगत शीतगृहों की तलपट्टी को Negotiable Instrument बनाने के लिए जोर दे रही है जिसके अनुसार शीतगृह द्वारा दी गई रसीद, आलू भण्डारण के बाद भण्डारणकर्ताओं को दी गई पक्की रसीद, बैंक अपने पास गिरवी रख सकेंगे और बैंक ब्याज दर पर लोन दे सकेंगे। इस विषय पर शीतगृहों ने अपना विरोध भी सरकार को भेजा है जो इस प्रकार है।

1. आलू नीति के अर्न्तगत सरकार का विशेष ध्यान Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (Act No.37 of 2007) के अन्तर्गत शीतगृहों की रसीद को Negotiable Instrument में बदलने की ओर है। इस प्रकिया में शीतगृहों को कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति है। इस सम्बन्ध में कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 17 विशेष ध्यान देने योग्य है। इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित समय के भण्डारण के बाद भी आलू निकासी के लिए शीतगृहों को 7 दिन और इंतजार करना पड़ता है व उसके बाद भण्डारणकर्ता को भण्डारित आलू निकालने के लिए नोटिस देना होता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 15 दिन निकल जाते हैं और यदि वह नोटिस सर्व (serve) नहीं हो पाता तब एक अनिश्चित समय तक इंतजार करना पड़ता है। यह उस समय बहुत अधिक नुकसानदेह व परेशानी वाला होता है जब बाजार में आलू के रेट नीचे गिर रहे हो या आलू खराब हो रहा हो। 31 अक्टूबर या 30 नवम्बर तक आलू भण्डारित करने के बाद तो आलू प्रायः खराब होने लगता है क्योंकि उसकी shelf life ही खत्म हो चुकी होती है।

ऐसी दशा में यदि भण्डारण की रसीद बैंक पर गिरवी रखी होगी तो बैंक का लोन व शीतगृह का भाड़ा दोनों ही डूब जायेंगे। आलू के भाव यदि आलू पर प्राप्त लोन, ब्याज व भाड़े से कम

हुए तो भण्डारणकर्ता आलू को छुड़ाने नहीं आयेगा, क्योंकि ऐसी दशा में भण्डारणकर्ता को पहले बैंक का पूरा ऋण चुकाना पड़ेगा, उसके बाद शीतगृह का भाड़ा देगा तभी उसको आलू की delivery दी जा सकेगी। ऐसे समय में भण्डारणकर्ता पर पूर्ण भुगतान के लिए धन नहीं होता ना ही उसकी ऐसे माल को छुड़ाने की इच्छा होती है। इस तरह बैंक का रुपया व शीतगृह का भाड़ा दोनों डूब जायेंगे और आलू की पूरी हानि अलग होगी। इस समय यदि भण्डारणकर्ता शीतगृहों में सीधा पहुँच जाता है तो उसके सामने शीतगृहस्वामी उसके आलू को बेच देता है और अपना भाड़ा व लोन काट कर बचा हुआ धन भण्डारणकर्ता को दे देता है।

इसलिए सरकार को आलू निकासी के नियम पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए जो कि विशेष कर बैंक में गिरवी रखे आलू के लिए 30 सितम्बर से अधिक नहीं होना चाहिए। आलू अन्य कृषि उत्पादों की तरह नहीं है जिसे निश्चित समय से अधिक भण्डारित किया जा सके। कुछ समय के बाद आलू सड़ने ना भी लगे तो भी उसकी गुणवत्ता में बहुत तेजी से फर्क आता है। जैसे आलू का रंग खराब होना और आलू मे झुर्रिया पड़ जाना आम बात है।

भण्डारण प्रभार पर व शीतगृहों पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च के बारे में विस्तार से चर्चा की गई जिस पर सभी जनपदों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी राय जाहिर की। शीतगृहस्वामी बिजली के बढ़ते रेट के बोझ, बढ़ती हुई पल्लेदारी व डीजल के बढ़ते हुए रेट से

बर्ड सेंक्चुरी के कारण सींगना में प्रोजेक्ट को नहीं मिली एनओसी

मथुरा में बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस

अमर उजाला ब्यूरो

- मथुरा के औरंगाबाद में उद्यान विभाग की जमीन चिह्नित
- प्रोजेक्ट को राज्य सरकार देगी जमीन, केंद्र सरकार देगी पैसा
- नीदरलैंड सरकार से तकनीकी सहयोग के लिए समझौता

आगरा। वर्षों की लड़ाई के बाद आलू बेल्ट को मिला सेंटर फॉर एक्सीलेंस अब मथुरा में बनेगा। बर्ड सेंक्चुरी के कारण सींगना में आलू के विकास के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं मिली है। सेंटर की स्थापना के लिए मथुरा के औरंगाबाद में उद्यान विभाग की भूमि चिह्नित की गई है। वहीं तकनीकी जानकारी के लिए नीदरलैंड की सरकार के साथ समझौता किया गया है।

बताते चलें कि आगरा के आलू उद्यमियों के अथक प्रयासों के कारण सेंटर फॉर एक्सीलेंस मिला है। यहां आलू के बीज शोधन से लेकर की प्रोसेसिंग तक के बारे में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पहले यह सेंटर आगरा के सींगना में लगना था लेकिन वन विभाग द्वारा बर्ड सेंक्चुरी को परिधि में आने के कारण इसके निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। अब इसके लिए मथुरा के औरंगाबाद में जमीन तलाश ली गई है। निर्माण के लिए राज्य सरकार करीब साठ एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार इसकी फंडिंग करेगी। इसको तकनीकी सहायता देने के लिए नीदरलैंड की सरकार से समझौता हो गया है। इससे यहां के किसानों को गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने और शोधन करने की सुविधा मिलेगी। आलू की प्रोसेसिंग के लिए भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

> सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए औरंगाबाद में जमीन चिह्नित कर ली गई है। तकनीकी सहायता के लिए नीदरलैंड से समझौता हो गया है।
>
> देवेंद्र नाथ पांडेय, उप निदेशक, लखनऊ
>
> सींगना के प्रोजेक्ट को बर्ड सेंक्चुरी के कारण अनुमति नहीं मिली है। फिर भी हमें खुशी है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस आगरा मंडल में है। इससे किसानों और उद्यमियों दोनों को फायदा होगा। राजेश गोयल, अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

(4) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जनवरी, 2013

विशेष परेशान थे। इसके साथ नये ईंधन अधिभार के लगाये जाने की खबर ने ही शीतगृहों को चिन्तित कर दिया। अधिकांश शीतगृहों की राय में वर्ष 2013 का भण्डारण प्रभार 180 रूपए प्रति कुन्तल सही ठहरता था। कुछ जनपद तो 200 रूपए कुन्तल की माँग कर रहे थे परन्तु समन्वय बनाने के लिए वा भण्डारणकर्ताओं की ओर भी ध्यान देते हुए अन्त में इस बात का निर्णय लेना पड़ा कि 175 रूपए प्रति कुन्तल का भण्डारण प्रभार 31 अक्टूबर, 2013 तक के लिए उचित रहना चाहिए। वैसे सारे शीतगृह अपना भण्डारण प्रभार स्वयं निर्धारित कर सकते है। वह किसी भी प्रकार से सलाहाकारी रेट मानने को बाध्य नही है।

देखो कैसा आलू की तरह फूल गया है, यह बात आपने हर मोटे आदमी के लिए सुनी होगी। आमतौर पर यह माना जाता है कि आलू या उससे बनी चीजें खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लखनऊ के एक कॉलेज के अध्ययन के मुताबिक आलू में वसा की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए इसे खाने से मोटापे का कोई खतरा नहीं है। पश्चिमी देशों में तो डायबिटीज के रोगियों को आलू कम कैलोरी वाले भोजन के रूप में दिया जाता है।

आलू खाने से...मुटापा नहीं!

डायबिटीज वालों को भी नहीं है नुकसान

सौजन्य से : **श्री हंसमुख जैन गाँधी**, गाँधी कोल्ड स्टोरेज, इन्दौर

(5) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जनवरी, 2013

पश्चिमी बंगाल के शीतगृहों की स्थिति :

हम पिछले अंक में बता चुके हैं कि 19 व 20 दिसम्बर, 2012 को कलकत्ता में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशनों की मीटिंग सम्पन्न हुई थी। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल शीतगृह संघ ने अपने यहाँ की स्थित का वर्णन किया। हमें आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक पश्चिम बंगाल सरकार ने भण्डारण प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की। इस समय वहाँ पर केवल 101 रू प्रति कुन्तल का प्रभार चल रहा है जिसके कारण पूरा शीतगृह उद्योग चरमरा गया है। जाने कितने शीतगृह बैंक को रुपया नहीं वापस कर पाने के कारण NPA हो गए हैं।

इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के कृषि मार्केटिंग सचिव सुब्राता विश्वास भी उपस्थित हुए। उन्होंने शीतगृहों की समस्याओं को पश्चिम बंगाल सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया। उनके द्वारा दिए गए भाषण पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष के भाषण वा हमारे भाषण के अंश जैसे The Bengal Post ने छापे हैं हम यहाँ आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के समाचार The Hindu, San Marg Patrika, Prablat Khabar वा कई बंगला समाचार पत्रों ने प्रकाशित किए हैं।

The Bengal Post
Kolkata, Friday, December 21, 2012

Govt to form joint action group to solve cold storage problems

OUR CORRESPONDENT
KOLKATA

The state government is planning to set up a joint action group with representatives of the cold storage association in order to mitigate a number of problems faced by the 425 cold storages, especially for potatoes in the state.

Agriculture marketing secretary Subrata Biswas indicated the formation of such a committee following demands by leaders of the cold storage association in the 48th annual general meeting of the forum. "The government is not keeping its eyes shut but rather, we are planning to form such a joint action group not only to look into the fair rent, but a complete package for revival of the cold storages needs to be worked out so that it can pave the way for investment in the state," said Biswas in his special address at the programme organised in a city hotel on Thursday.

In his presidential address, West Bengal Cold Storage Association office-bearer Rampada Paul mentioned a bunch of serious problems which are leading to the decline of the cold storage industry in the state. "The state government has overlooked the manifold increase in cost of operations over the last three years in fixing the fair rent for the last two years. Despite the steep increase in operational costs, the rent for cold storage units has not been revised since February 2010," said Paul.

After the procurement of potatoes, the vendors keep the sacks of potatoes in cold storage at a rate of Rs 10 per 50 kg sack and the forum demanded a hike in this fair rent.

Mahindra Swarup, president, Federation of Cold Storage Associations of India, attended the programme and said: "Other state governments support the cold storage business a lot in terms of transport and renovation subsidy but I found the scenario is worst in Bengal. Although business is down all over India due to cost escalation, even the installation of storage with 5,000 metric tonne capacity cannot sustain in the present scenario."

(6) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जनवरी, 2013

जनपद स्तर पर शीतगृह संघ की मीटिंग के सम्बन्ध में :

हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि कासगंज शीतगृह संघ ने कासगंज में अपनी एसोसिएशन की मीटिंग की जो कि बहुत सफल रही। सारे शीतगृहस्वामी बढ़े हुए खर्चे के प्रति काफी चिन्तित व सजग थे, उन्होंने 10 से 15 रुपए, पैकेट भाड़ा बढ़ाने की माँग भी की है। हम इस मीटिंग के चित्र भी प्रकाशित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि और संघ भी इस प्रकार की मीटिंग अपने यहाँ करें और उनका विवरण हमें भेजें जिन्हें हम पत्रिका में प्रकाशित कर सकें। इस मीटिंग में निम्न शीतगृह स्वामी उपस्थित रहें।

मीटिंग में विनोद अग्रवाल (श्री रामशरणम कोल्ड स्टोर, खैर), अनिल जी अग्रवाल (अग्रवाल कोल्ड स्टोर, अतरौली), मयंक अग्रवाल (बाबा कोल्ड स्टोर, जलेसर), विपन वर्मा एवं प्रजापालन वर्मा 'विधायक' (श्री गंगाप्रसाद शीतगृह, एटा), वीरेश जती यादव (किसान कोल्ड स्टोर, एटा), वीरेन्द्र रावत (श्री दुग्ध डेरी एवम् कोल्ड स्टोर), पराग अग्रवाल (श्री रामनिवास जी कोल्ड स्टोर, अलीगंज), अमित शर्मा (महालक्ष्मी कोल्ड स्टोर उझानी), अवधेश कुमार अग्रवाल (श्री बालाजी आइस कोल्ड स्टोर, गोपी–अलीगढ़), मो. मुवीन अहमद (स्टैन्डर्ड कोल्ड स्टोरेज, गंजडुण्डवारा), सुबोध मित्तल (माँ गायत्री कोल्ड स्टोर, अमांपुर), निशीथ गर्ग (पिनाकपाणी कोल्ड स्टोर, कासगंज), विनोद गुप्ता (जय अम्बे कोल्ड स्टोर, कासगंज), अरुण माहेश्वरी (गंगा कोल्ड स्टोर, कासगंज), विनीत बंसल (किसान कोल्ड स्टोर, कासगंज), मुकेश शर्मा (राज कोल्ड स्टोर, कासगंज), नरेश जी गोयल (जे.बी. कोल्ड स्टोरेज, कासगंज) ने सहभागिता ली।

कांसगंज शीतगृह संघ मीटिंग का एक दृश्य

कांसगंज शीतगृह संघ मीटिंग का एक दृश्य

मेगा फूड पार्क की स्थापना :

भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि किस प्रकार कृषि व उद्यान के उत्पादित पदार्थो का सही प्रयोग किया जा सके, उन्हे सड़ने से बचाया जाय व उसे इस योग्य बनाया जाय कि बाजार में उसकी ज्यादा कीमत मिल सके। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना में उद्यमियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उन्हें एक जगह सड़क, जल, जल निस्तारण, विद्युत आदि की व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाता है और धन भी बहुत खर्च होता है। इन सब चीजों को जुटाने में सरकार ने मदद की सोची है और मेगा फूड पार्क के स्थापना का विचार बनाया है। इनमें एक तरह के कई उद्योग एक जगह काम कर सकेंगे जहाँ उन्हें उपरोक्त बताई सुविधा के अतिरिक्त ट्रकों की, रेल की, लाने ले जाने की सुविधा, कच्चा माल को ठीक करने की सुविधा भी शामिल होगी। ऐसा भी किया जा रहा है कि उत्पादन की गुणवत्ता बनाने के लिए एक जगह कंट्रोल लैब बनाई जाए और बिक्री करने के लिए भी संयुक्त रूप से बिक्री केन्द्र रखे जाए।

अभी यह पूरी स्कीम श्री राजेश गोयल, सचिव के माध्यम से National Horticulture Board से प्राप्त हुई जिसे हमने वेब साइट पर भी दे दिया है। इसे आप हमारी वेब साइट पर पढ़ सकते हैं या इसमें दिए हुए सलाहकारों से भी सलाह ले सकते है। हमने भी इस स्कीम को बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा व समझा है, जहाँ तक हमने समझा है किसी भी उद्योग का साइज कम से कम 25 करोड़ रूपए होना चाहिए जिस पर 10 करोड़ रूपए तक का अनुदान मिल सकेगा। अनुदान की शर्तें क्या होगी यह वेब साइट पर देखिए। अभी यह मेगा फूड पार्क जगदीशपुर में प्रस्तावित है। यदि अधिक उद्योगों के द्वारा माँग की गई तो इसे आगरा में भी लगाया जा सकता है।

WDRA पर PHD Chamber द्वारा आयोजित मीटिंग

PHD Chamber of Commerce ने 31.1.2013 को एक मीटिंग का आयोजन किया, यह मीटिंग शीतगृहों व अन्य वेयरहाउसिंग रसीदों को Negotiaable Instrument बनाने के सम्बन्ध में थी। अतः हमें भी आमंत्रित किया गया। माननीय आनन्द सिंह, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश राय, आई.ए.एस. सेवानिवृत्त, चैयरमैन, व्यू.डी.आर.डी.ए. भारत सरकार, श्री करनैल सिंह, आई.ए.

एस. सेवानिवृत्त, सदस्य, व्यू.डी.आर.डी.ए., डा. आर.के. शर्मा, डायरेक्टर, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, श्री ओ.एन. सिह., आई.ए.एस., डायरेक्टर, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। व्यू.डी.आर.ए. की स्कीम में भण्डारणकर्ता को शीतगृह या वेयरहाउसिंग की रसीद पर बैंक सीधे 70 प्रतिशत तक लोन दे देंगे, जिस पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। इसकी सीमा 3 लाख रूपए होगी व सड़ने वाले पदार्थ पर समय सीमा छह माह के भण्डारण से अधिक नहीं होगी।

शीतगृह या वेयरहाउसिंग को अपने संस्थान का accredetion यानी इस कार्य के लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी। इस मान्यता के लिए शीतगृहों को कई नियमों से गुजरना होगा, जैसे उनके यहाँ भण्डारण व्यवस्था दिए हुए मानकों के अनुरूप है, अग्नि शमन उपकरण आदि सही लगे है व मशीन चालकों आदि की व्यवस्था सही रूप से है इत्यादि। इसके बाद शीतगृहों की रसीद पर बैंक सीधे लोन दे देगा। शीतगृहस्वामी को फिर कोई गारण्टी नहीं देनी होगी।

1. शीतगृहों का पक्ष रखते हुए हमने कहा कि इस सारी प्रक्रिया में शीतगृहों के भाड़े की सुरक्षा का कोई नियम नहीं बना है। यदि भण्डारित आलू का रेट लोन व भण्डारण प्रभार के योग से कम हो जाता है तो भण्डारणकर्ता भण्डारित माल को छुड़ाने ही नहीं आयेगा।
2. भण्डारित आलू की डिलीवरी लेते वक्त भण्डारणकर्ता पर पूरा लोन एक साथ चुकता करने का पैसा ही नहीं होता वह बैंक का लोन किस प्रकार चुका पायेगा।
3. शीतगृह को तो शीतगृह चलाने व उत्पाद को भण्डारित रखने की बाध्यता 30 नवम्बर तक की है। तब तक शीतगृहस्वामी के सामने भण्डारित आलू की कीमत उस पर होने वाले प्रभार के बराबर तो रह जाती है। लोन आदि का रुपया डूब जाता ही जाता है। इस प्रकार बैंक का रुपया काफी मात्रा में डूब जायेगा।
4. निश्चित तिथि समाप्त होने के बाद भी बैंक के लोन वापस लेने की प्रक्रिया इतनी धीरे होती है कि आलू उस स्थिति में पहुँच जायेगा जबकी उससे सही पैसा वसूल नहीं हो सकेगा।

हमारी तरफ से सही और विस्तृत सुझाव देने के लिए हमने चैयरमैन श्री दिनेश राय से अनुरोध किया है कि शीतगृहस्वामियों की एक मीटिंग बैकों के साथ कराई जाए जिससे बैंक और शीतगृह अपनी–अपनी समस्याओं को सुलझा सकें।

फार्म 4

❑ प्रकाशन स्थान	:	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशन अवधि	:	मासिक
❑ मुद्रक का नाम	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र स्वरूप
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ जो व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हो तथा जो समस्त पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

मैं महेन्द्र स्वरूप एततद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिए हुए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर

महेन्द्र स्वरूप

आगरा में हुई मीटिंग के सम्बन्ध में :

आगरा में हुई मीटिंग जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व के उद्यमियों को आमंत्रित किया कि वह उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाए। इस मीटिंग में नीदरलैण्ड (Netherland) की बीज सम्बन्धी विशेषज्ञों व कम्पनियों ने भी माँग लिया। इन विशेषज्ञों ने नीदरलैण्ड से उत्तम किस्म के आलू के बीज उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। इस सम्बन्ध में हम समाचार पत्र में छपी खबर को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

आलू उत्पादक किसानों को सौगात

खुशखबरी

- नीदरलैंड देगा उत्तर प्रदेश को विश्वस्तरीय बीज तकनीकी
- दुनिया के सबसे बड़े आलू मेले में आगरा को मिला आमंत्रण

द सी एक्सप्रेस न्यूज़

होटल रेडिसन में मंगलवार को नीदरलैंड के विशेषज्ञों के साथ आलू उत्पादन पर चर्चा करते हुए आलू व्यवसायी और कोल्ड स्टोर मालिक। फोटोः द सी एक्सप्रेस न्यूज़

आगरा। देश की कुल पैदावार का 25 प्रतिशत आलू उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश के लिए पार्टनरशिप समिट-2013 बड़ी खुशी लेकर आया है। नीदरलैंड के विशेषज्ञों की टीम ने उत्तर प्रदेश के आलू की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बनाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए सहमति दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार नीदरलैंड के वैज्ञानिकों की टीम उत्तर प्रदेश में आलू बुवाई के समय पहुंचेगी। इसके साथ ही यहां के किसानों को यूरोप के सबसे बड़े मेले पुटैटो यूरोप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस साल 10 से 12 सितम्बर तक दुनिया का ये सबसे बड़ा आलू मेला नीदरलैंड में हो रहा है।

नीदरलैंड एग्रो फूड एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर एवं अन्य अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को समिट से पूर्व आगरा और अलीगढ़ के आलू उत्पादक किसानों एवं कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आलू और से उससे बनने वाले उत्पाद की गुणवत्ता, आलू व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यहां के आलू उत्पादक किसानों की मांग पर नीदरलैंड के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में टिशू कल्चर लैब की स्थापना पर अपनी सहमति जता दी है। टिशू कल्चर लैब में विश्व स्तरीय आलू के बीज की पैदावार की जा सकेगी, जिससे दूसरे देशों में आलू के निर्यात को बल मिल सकेगा। अभी तक भारत का आलू बेहतर गुणवत्ता के बावजूद विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप नहीं होते। यही कारण है कि इसका निर्यात भी आशा के अनुरूप नहीं हो पाता। वर्तमान में आलू की प्रोसेसिंग से बनने वाले उत्पादों का ही निर्यात हो पा रहा है। नीदरलैंड के सेंटर के निदेशक मौरिस लेजटेन ने भरोसा दिया कि जिस समय उत्तर प्रदेश में आलू की बुवाई शुरू होगी, उस समय सेंटर के वैज्ञानिकों की टीम भारत आकर यहां के आलू बीज की गुणवत्ता के साथ बुवाई का तरीका, जलवायु आदि पर रिसर्च करेगी, जिससे उच्च गुणवत्ता के बीज पर काम शुरू किया जा सके। इसके साथ ही सेंटर के निदेशक ने आलू उत्पादक किसानों को नीदरलैंड में होने वाले पुटैटो यूरोप नामक आलू मेले में आने का भी आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान वहां पर आलू पैदावार के तरीके की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बताया जाएगा कि किस प्रकार अच्छी गुणवत्ता का आलू बीज तैयार किया जा सकता है। होटल रेडिसन में हुई बैठक में आगरा कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन सिंहल, महासचिव राजेश गोयल, राकेश गर्ग, मुकेश अग्रवाल, अजय गुप्ता, विवेक जुरैल, उपेन्द्र, अलीगढ़ से मुकेश सिंघल आदि ने भाग लिया।

इसी मीटिंग में आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन में अमेरिका के कृषि सम्बन्धी सचिव से हुई वार्ता के अंश भी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

फूड प्रोसेसिंग बेहतर बनाने में अमेरिका से मिलेगी मदद

आगरा। फूड प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने क लिए आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने समिट के दौरान अमेरिकन डेलीगेट्स से मुलाकात कर आधुनिक तकनीक में सहयोग माँगा। अमेरिका के अंडर सेक्रेट्री रार्बट हारमेट्स ने वहाँ की यूनिवर्सिटी से टाइअप कराने का आश्वासन दिया।

आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन सिंघल और महामंत्री राजेश गोयल के नेतृत्व में अमेरिका के इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी और इनवॉयरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेट्री रार्बट हारमेट्स से मुलाकात कर फूड प्रोसेसिंग को बेहतर करने के लिए तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। रार्बट हारमेट्स ने उन्हें सकारात्मक जवाब दिया। इसके लिए शीघ्र ही सहयोग करने की अपील की। मौके पर अमेरिकन, डेलीगेट्स में डेबिट जैनी, अमिता मोदी, डंकन व जुएदा मौजूद रहीं, वहीं प्रोग्राम कोआर्डिनेटर भवेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, अजय गुप्त आदि लोग मौजूद रहे।

आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों की अमरिकन अण्डर सेक्रेट्री के साथ हुई बैठक के दृश्य जिसमें श्री राजेश गोयल आगरा ताजमहल की एक कलाकृति को भेट करते हुए।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित